

(2013) 6 एस.सी.आर 391

एन. नारायणन

बनाम

न्याय अधिकारी, एसईबीआई

(सिविल अपील संख्या 4112-4113/2013)

26 अप्रैल 2013,

(के.एस राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा जे.जे)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 एस 12 ए और धारा 15 एचए आर/डब्ल्यू एस धारा 15 जे - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार का निषेध) विनियम, 2003 - विनियमन 3(बी)}, 3(सी), 3(डी)}, 4(1), 4(2)(ए)}, 4(2)(ई)}, 4(2)(एफ)}, 4(2)(के)}, 4(2)(आर) - प्रतिभूति बाजार - बाजार का दुरुपयोग - अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप, जो प्रमोटर के साथ-साथ पूर्णकालिक निदेशक भी था विचाराधीन कंपनी का, आयोजित प्रकटीकरण और पारदर्शिता दो स्तंभ हैं जिन पर बाजार की अखंडता टिकी हुई है। जिन कंपनियों की प्रतिभूतियों का सार्वजनिक बाजार में कारोबार होता है, उनके बारे में जानकारी का खुलासा कंपनियों की प्रतिभूतियों के सटीक मूल्य निर्धारण और बाजार के कुशल संचालन के लिए महत्वपूर्ण है

तथ्यों पर, निवेशकों का विश्वास खत्म हो गया और व्यक्तिगत लाभ और उपलब्धियों के लिए बाजार का दुरुपयोग किया गया था, संबंधित कंपनी के निदेशक उचित देखभाल और परिश्रम करने के अपने कर्तव्य में विफल रहे और कंपनी को आंकड़े गढ़ने और झूठे खुलासे करने की अनुमति दी। निदेशकों ने कृत्रिमता पैदा की और कंपनी के वित्तीय परिणामों में हेरफेर किया जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के शेयरों की कीमत में वृद्धि हुई और फिर वित्तीय संस्थानों से पर्याप्त धन जुटाने के लिए अपने शेयरों को कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई कीमतों पर गिरवी रख दिया। सेबी अधिनियम की धारा १२ए सपाठित नियम ३ और ४ २००३ नियम का स्पष्ट उल्लंघन जिसका मूलतः इरादा बाजार की अखंडता को बनाए रखना और बाजार के दुरुपयोग को रोकना है। अपीलकर्ता-निदेशक और अन्य निदेशकों का आचरण कपटपूर्ण था और प्रतिभूतियों से संबंधित उनके द्वारा अपनाई गई प्रथाएं अनुचित थीं, जिसके कारण एस में निहित दंड प्रावधान लागू हुए 15 एचए आरएलडब्ल्यू एस. सेबी अधिनियम की धारा 15 सेबी ने अपीलकर्ता-निदेशक को दो साल के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या व्यवहार करने, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने और किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक होने से दो साल के लिए रोक दिया है। न्यायनिर्णायक अधिकारी ने सेबी अधिनियम के उल्लंघन के तहत 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया मैक्सिम एक्टा

एक्सटीरिया इंडिकेंट इंटिरियरा सेक्रेटा (जिसका अर्थ है कि बाहरी क्रियाएं आंतरिक रहस्यों को उजागर करती हैं)

कंपनी कानून ,सूचीबद्ध कंपनियाँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और निदेशक , निदेशकों के दायित्व सी धारित सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशकों के दायित्व विशेष रूप से कठिन है, खातों को मंजूरी देने के लिए निदेशकों का अतिव्यापी दायित्व केवल तभी जब वे संतुष्ट हों कि वे सही हैं और संबंधित अवधि के लिए लाभ या हानि का निष्पक्ष दृष्टिकोण और कंपनी की सही वित्तीय स्थिति।

कंपनी कानून प्रकटीकरण और पारदर्शिता की आवश्यकता माना गया कंपनी अधिनियम कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी पर पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए खातों की किताबें रखने का दायित्व डालता है। कंपनी की प्रतिभूतियों के सटीक मूल्य निर्धारण के लिए कंपनी के बारे में जानकारी का खुलासा महत्वपूर्ण है। और बाजार की अखंडता के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को कंपनी के लेनदेन को दिखाना और समझाना चाहिए, इसे उचित सटीकता के साथ वित्तीय स्थिति का खुलासा करना चाहिए, किसी भी समय खातों को सही और निष्पक्ष दृश्य देना चाहिए

शेयर और प्रतिभूतियाँ - बाज़ार दुरुपयोग - क्या है - बाज़ार दुरुपयोग के प्रभाव पर चर्चा की गई।

शेयर और प्रतिभूतियां - प्रतिभूति बाजार - सेबी, बाजार नियामक - सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों और अंदरूनी सूत्रों के अवसरवादी व्यवहार के खिलाफ व्यक्तिगत और सामूहिक निवेशकों की रक्षा करना सेबी का कर्तव्य है ताकि बाजार की अखंडता की रक्षा की जा सके - प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कर्तव्य।

अपीलकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी का प्रमोटर होने के साथ-साथ पूर्णकालिक निदेशक भी था। कंपनी में अपीलकर्ता सहित नौ निदेशक थे और यह प्रदर्शनी (थिएटर), फिल्म और टेलीविजन, सामग्री उत्पादन के व्यवसाय में शामिल थी। ,वितरण, आतिथ्य, खाद्य और पेय, एनीमेशन और गेमिंग और सिने विज्ञापन आदि। कंपनी के शेयर प्रासंगिक समय पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर सूचीबद्ध थे।

सेबी के जांच विभाग ने देखा कि कंपनी ने अपने खातों में गंभीर अनियमितताएं की थीं और वित्तीय विवरणों में बढ़ा-चढ़ाकर मुनाफा और राजस्व दिखाया था और ऐसे झूठे वित्तीय विवरणों के आधार पर कंपनी के शेयरों में निवेश करने के लिए आम जनता को लुभाया और इस तरह उल्लंघन किया। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार का निषेध) विनियम, 2003 के प्रावधान। अपीलकर्ता और अन्य निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि उन्होंने प्रतिभूतियों

की धारा 12 ए का उल्लंघन किया है और भारतीय विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और विनियम 3(बी), 3(सी), 3(डी), 4(1), 4(2)(ए), 4(2)(ई), 4(2)(एफ); 2003 विनियमों की 4(2)(के), 4(2)(आर)। इसके अलावा, सेबी के नियम 4(1) (न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने और जुर्माना लगाने की प्रक्रिया) नियम, 1995 के तहत एक नोटिस निदेशकों को यह बताने के लिए जारी किया गया था कि क्यों न सेबी अधिनियम की धारा 15 एच.ए के तहत जुर्माना लगाया जाए। अधिनियम के प्रावधानों का कथित उल्लंघन।

अपीलकर्ता ने कहा, हालांकि वह कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक थे, लेकिन वह केवल कंपनी के मानव संसाधन विभाग को संभाल रहे थे और कर्मियों की भर्ती, प्रशिक्षण और टीम निर्माण में पूरी तरह से तल्लीन थे। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि उन्होंने वित्तीय मामलों में केवल ऑडिटर के बयानों पर भरोसा किया था और इसलिए सेबी अधिनियम और 2003 के नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं थे।

हालाँकि, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य (डब्ल्यूटीएम) ने माना कि निदेशक सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 12 ए और विनियमन 3(बी), 3(सी), 3(डी), 4(1) के उल्लंघन के लिए दोषी थे। , 2003 विनियमों के 4(2)(ए), 4(2)(ई), 4(2)(एफ), 4(2)(के), 4(2)(आर)। अपीलकर्ता को किसी भी तरीके से प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या व्यवहार करने या

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने और किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक होने से दो साल की अवधि के लिए रोकने का आदेश पारित किया गया था, और इसके अलावा, सेबी अधिनियम की धारा 15 एच.ए के तहत अपीलकर्ता पर 50 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। आदेश की पुष्टि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा की गई थी, जिसकी वैधता सेबी अधिनियम की धारा 15 के तहत इस अपील का विषय थी।

अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा

अभिनिर्धारित किया: 1. निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करके पूंजी बाजार में निवेशकों का विश्वास काफी हद तक कायम रखा जा सकता है। प्रकटीकरण और पारदर्शिता दो स्तंभ हैं जिन पर बाजार की अखंडता टिकी हुई है। मामले के तथ्यों से पता चलता है कि निवेशकों का विश्वास कैसे खत्म हो गया है और व्यक्तिगत लाभ और उपलब्धियों के लिए बाजार का दुरुपयोग कैसे किया गया है। बाजार का दुरुपयोग अब भारत के सुरक्षा बाजार में एक आम बात बन गई है और यदि इस पर ठीक से अंकुश नहीं लगाया गया, तो इसका परिणाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के मूल उद्देश्य और उद्देश्य को विफल करना होगा, जिसका उद्देश्य सुरक्षा करना है। प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना। जिन कंपनियों की प्रतिभूतियों का सार्वजनिक बाजार में कारोबार होता है, उनके बारे में जानकारी का

खुलासा कंपनियों की प्रतिभूतियों के सटीक मूल्य निर्धारण और बाजार के कुशल संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। मौजूदा मामले में, कंपनी के निदेशकों ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार अभ्यास का निषेध) विनियमों के विनियम 3 और 4 के साथ पढ़े जाने वाले सेबी अधिनियम की धारा 12 ए के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया था। 2003. सेबी ने अपीलकर्ता को उस आदेश की तारीख से दो साल की अवधि के लिए किसी भी तरह से किसी भी प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या व्यवहार करने, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने और किसी भी सूचीबद्ध के निदेशक होने से रोक दिया। कंपनी और निर्णायक अधिकारी ने सेबी अधिनियम की धारा 1 15 एचए के तहत 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। (पैरा 1,10,28,42) 400-ए-बी; 403-सी- सी. डी; 413-सी-डी; 418-एफ-जी,

पाल्मर्स कंपनी कानून, 25 वां संस्करण (2010), खंड 2 और गॉवर एंड डेविस - मॉडेम कंपनी कानून के सिद्धांत, 9 वां संस्करण (2012) - संदर्भित।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस और निदेशक

2. कंपनी अधिनियम के विनियमों के साथ पढ़ा जाने वाला सेबी अधिनियम यह संकेत देगा कि सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशकों के दायित्व

विशेष रूप से कठिन हैं, खासकर जब निदेशक मंडल कंपनी के प्रदर्शन के लिए शेयरधारकों और शेयरधारकों के प्रति खुद को जवाबदेह बनाता है। अपने खातों और वित्तीय विवरणों के उत्पादन के लिए, विशेषकर जब कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी हो। (पैरा 29), (413-ई-एफ),

3. वार्षिक रिकॉर्ड और रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी निदेशकों पर डाली जाती है और उन खातों में सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रतिबिंबित होना चाहिए। निदेशकों का प्रमुख दायित्व यह है कि वे खातों को तभी मंजूरी दें जब वे संतुष्ट हों कि वे संबंधित अवधि के मुनाफे या एलके और कंपनी की सही वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं। निदेशकों से अपेक्षा की जाती है कि वे कंपनी की ओर से अपनी शक्ति का प्रयोग अत्यंत सावधानी, कौशल और परिश्रम से करें। (पैरा 32,33) (414-सी-डी), आधिकारिक परिसमापक बनाम पी.ए. तेंदुलकर (1973) 1 एससीसी 602०:1973 (3) एस.सी.आर 364 पर निर्भर।

4. इस मामले में तथ्यों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संबंधित कंपनी के निदेशक उचित देखभाल और परिश्रम करने के अपने कर्तव्य में विफल रहे और कंपनी को आंकड़े गढ़ने और झूठे खुलासे करने की अनुमति दी। तथ्यों से संकेत मिलता है कि उन्होंने राजस्व, लाभ, प्राप्य, जमा आदि में कई लाल झंडों को नजरअंदाज कर दिया है, जो एक विवेकशील व्यक्ति के ध्यान से बच नहीं जाना चाहिए था। तथ्यों ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि कंपनी ने झूठी कॉर्पोरेट घोषणा की थी जिसमें कहा गया था कि उसने

802 थिएटरों के साथ समझौता किया था और झूठी कॉर्पोरेट घोषणा में थिएटरों से संबंधित अग्रिम, सुरक्षा जमा और आय से संबंधित गलत आंकड़े दिए गए थे जो अस्तित्व में नहीं थे। दिखाई गई जमा राशि वास्तविक नहीं थी, बल्कि बैलेंस शीट में प्राप्तियों को छिपाने के लिए केवल बही प्रविष्टियाँ थीं। (पैरा 31,34, 413 एच; 414 ए-बी, एफ-जी)

प्रतिभूति बाजार - बाजार का दुरुपयोग

5. बाजार दुरुपयोग का अर्थ चालाकीपूर्ण और भ्रामक उपकरणों के उपयोग से है, जो गलत या भ्रामक जानकारी देता है, ताकि निवेशकों को गलत आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जो दुरुपयोग करने वालों के लिए गलत माना जाता है। बाजार का दुरुपयोग आर्थिक विकास को खराब करता है और निवेशकों का विश्वास खो देता है। सेबी अधिनियम का उद्देश्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और विकास को बढ़ावा देना और प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना है, ताकि प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित, स्वस्थ विकास को बढ़ावा दिया जा सके और निवेशकों की सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। विनियम 2003 के विनियम 3 और 4 के साथ पठित सेबी अधिनियम की धारा 12 ए का उद्देश्य अनिवार्य रूप से बाजार अखंडता को संरक्षित करना और बाजार दुरुपयोग को रोकना है। वैधानिक प्रावधान उन स्थितियों से निपटते हैं जहां कोई व्यक्ति, जो प्रतिभूतियों में व्यापार करता है, किसी कार्रवाई के प्रभाव का लाभ उठाता है। जोड़-तोड़, बाजार पर प्रत्याशित प्रभाव के

परिणामस्वरूप कृत्रिमता का निर्माण होता है। इसे कंपनी के राजस्व, लाभ, सुरक्षा जमा और प्राप्तियों को बढ़ाकर प्राप्त किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के शेयरों की कीमत बढ़ जाती है। फिर निवेशकों को लालच दिया जाता है उपरोक्त उपकरणों का उपयोग करके उन हेरफेर किए गए बढ़ाए गए परिणामों पर अपने निवेश निर्णय लेने के लिए जो बाजार का दुरुपयोग होगा। (पैरा 35)(415-ई-जी)

6. तथ्यों पर यह स्पष्ट रूप से पाया गया है कि कंपनी के निदेशकों ने कंपनी के राजस्व, लाभ, सुरक्षा के बढ़े हुए सी आंकड़े पेश करके कृत्रिमता पैदा की है। जमा और प्राप्त और कंपनी के वित्तीय परिणामों में हेरफेर के परिणामस्वरूप कंपनी के शेयरों की कीमत में वृद्धि हुई और कंपनी के प्रमोटरों ने वित्तीय संस्थानों से पर्याप्त डी फंड जुटाने के लिए अपने शेयरों को गिरवी रख दिया। इसलिए, अपीलकर्ता और अन्य का आचरण धोखाधड़ीपूर्ण था और प्रतिभूतियों से संबंधित उन्होंने जो प्रथाएं अपनाई थीं, वे अनुचित थीं, जिसके कारण सेबी अधिनियम की 15 जे के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 15 एच.ए में निहित दंड प्रावधानों को लागू किया गया (पैरा 36) (415 -एच; 416-ए-बी)

प्रकटीकरण और पारदर्शिता

7. कंपनी अधिनियम पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी पर खातों की किताबें रखने का

दायित्व डालता है। कंपनी की प्रतिभूतियों के सटीक मूल्य निर्धारण और बाजार की अखंडता के लिए कंपनी के बारे में जानकारी का प्रकटीकरण एफ महत्वपूर्ण है। कंपनी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को कंपनी के लेनदेन को दिखाना और समझाना चाहिए, इसे किसी भी समय उचित सटीकता के साथ वित्तीय स्थिति का खुलासा करना चाहिए, और निदेशकों को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना चाहिए कि बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते वैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे। वे वृत्तान्त सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। (पैरा 38) (416-एफ-एच; 417-ए-बी)

8. वर्तमान मामले में, कंपनी के निदेशकों और मुख्य वित्तीय अधिकारियों ने कंपनी के जाली और भ्रामक परिणाम प्रकाशित किए थे, विभिन्न तिमाही वित्तीय परिणाम और वर्ष 2007-08 के वार्षिक परिणाम, स्टॉक को सूचित किए गए थे- एक्सचेंजों में कंपनी के राजस्व, लाभ, सुरक्षा जमा और प्राप्त के बढ़े हुए आंकड़े और वित्तीय विवरण शामिल थे जिन पर निवेशकों द्वारा निवेश निर्णय लेने में भरोसा किया गया था, जो कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित नहीं करता था। अपीलकर्ता, माना जाता है कि, कंपनी का पूर्णकालिक निदेशक था, जहां तक वार्षिक खातों, बैलेंस-शीट और वित्तीय विवरण तैयार करने और वार्षिक आम बैठक में कंपनी के समक्ष रखने और रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल करने का संबंध था। कंपनियों के साथ-साथ सेबी के समक्ष, कंपनी के निदेशकों की अधिक जिम्मेदारी होती है, खासकर

जब कंपनी एक पंजीकृत कंपनी हो। कंपनियों के निदेशकों, विशेष रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों के पास कंपनी की आंतरिक जानकारी, जैसे कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभांश दरें, वार्षिक खाते आदि तक पहुंच होती है। जहां तक इस मामले का सवाल है, कृत्रिम रूप से अपने शेयरों को गिरवी रखने का बाद का आचरण बढ़े हुए वित्तीय परिणामों के आधार पर बढ़ी हुई कीमतें और उन पर ऋण उठाना यह दर्शाता है कि उन्होंने जानबूझकर और पूरी जानकारी के साथ अवैधता की है और इसलिए एकटा एक्सटीरिया इंडिकेंट इंटिरियर सीक्रेटा का सिद्धांत (जिसका अर्थ है कि बाहरी क्रियाएं आंतरिक रहस्यों को प्रकट करती हैं) का सिद्धांत पूरी ताकत से लागू होती है। (पैरा 39, 40, 41) (417-एफ-जी; 418-ए-ई)

सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और अन्य (2013) 1 एससीसी 1 - पर भरोसा किया।

चेतावनी

9.1. बाजार नियामक सेबी को चालाकीपूर्ण और भ्रामक उपकरणों, अंदरूनी व्यापार आदि में लिप्त कंपनियों और उनके निदेशकों से सख्ती से निपटना होगा अन्यथा वे प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के अपने कर्तव्य में विफल हो जाएंगे। आर्थिक अपराध एक गंभीर अपराध है, जिससे यदि ठीक से निपटा नहीं गया, जैसा

कि होना चाहिए, तो न केवल देश की आर्थिक वृद्धि प्रभावित होगी, बल्कि वास्तविक निवेशकों द्वारा विदेशी निवेश का प्रवाह भी धीमा हो जाएगा और भारत के प्रतिभूति बाजार पर भी कलंक लगेगा। सेबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धोखाधड़ी, छल, कृत्रिमता का इस देश के प्रतिभूति बाजार में कोई स्थान नहीं है और बाजार सुरक्षा हमारा आदर्श वाक्य है। सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों और अंदरूनी सूत्रों के अवसरवादी व्यवहार के खिलाफ व्यक्तिगत और सामूहिक निवेशकों की रक्षा करना सेबी का कर्तव्य है ताकि बाजार की अखंडता की रक्षा की जा सके। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी यह गंभीर कर्तव्य है कि वे प्रतिभूति बाजार पर अपने पूर्वानुमानों में जनता, जो वर्तमान और संभावित निवेशक हैं, को गुमराह न करें। प्रतिभूतियों में स्थिति से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सुरक्षा बाजार में कंपनी की स्थिति पर मीडिया प्रक्षेपण बाजार का दुरुपयोग होगा, कृत्रिमता पैदा करेगा। (पैरा 43,44) (419-ए-एफ)

केस लॉ संदर्भ

(2013) 1 एस.सी.सी पैरा 25

1973 (3) एस.सी.आर 364 पैरा 33

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4112-
4113/2013

अपील संख्या 28 और 29 में मुंबई स्थित प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 05.10.2012 के निर्णय और आदेश से।

सिबो शंकर मिश्रा, एम.के. पांडे अपीलकर्ता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया।

के.एस. राधाकृष्णन, जे. 1. भारत के पूंजी बाजार में हाल के दिनों में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है, जिसमें विशेष रूप से जनता की बढ़ती भागीदारी शामिल है। निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करके पूंजी बाजार में निवेशकों का विश्वास काफी हद तक कायम रखा जा सकता है। प्रकटीकरण और पारदर्शिता दो स्तंभ हैं जिन पर बाजार की अखंडता टिकी हुई है। मामले के तथ्यों से पता चलता है कि निवेशकों का विश्वास कैसे खत्म हो गया है और व्यक्तिगत लाभ और उपलब्धियों के लिए बाजार का दुरुपयोग कैसे किया गया है।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (संक्षेप में सेबी अधिनियम) की धारा 15 जेड के तहत गारंटीकृत इस न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को अपील संख्या 28 और 29 में पारित दिनांक 5.10.2012 के एक संयुक्त आदेश को चुनौती देते हुए लागू किया गया है। 2012 में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई (संक्षेप में न्यायाधिकरण के लिए) द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए सेबी ने 18 अप्रैल, 2011 को पारित आदेश को बरकरार रखा, जिसमें अपीलकर्ता को

प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या लेनदेन करने से दो साल की अवधि के लिए रोक दिया गया था और आदेश पारित किया गया था। निर्णय अधिकारी ने 28 जुलाई 2011 को सेबी अधिनियम की धारा 15 भू. के तहत 50 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया।

3. अपीलकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी मेसर्स पिरामिड सैमीरा थिएटर लिमिटेड (पीएसटीएल) का प्रमोटर होने के साथ-साथ पूर्णकालिक निदेशक भी था। पीएसटीएल के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) में सूचीबद्ध थे।) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) प्रासंगिक समय पर। कंपनी प्रदर्शनी (थिएटर), फिल्म और टेलीविजन, सामग्री उत्पादन, वितरण, आतिथ्य, खाद्य और पेय, एनीमेशन और गेमिंग और सिने विज्ञापन आदि के व्यवसाय में शामिल थी। कंपनी में अपीलकर्ता सहित नौ निदेशक थे। सेबी के जांच विभाग ने पाया कि कंपनी ने अपने खातों में गंभीर अनियमितताएं की थीं और वित्तीय विवरणों में बढ़ा-चढ़ाकर मुनाफा और राजस्व दिखाया था और ऐसे झूठे वित्तीय विवरणों के आधार पर आम जनता को कंपनी के शेयरों में निवेश करने के लिए लुभाया था, जिससे सेबी का उल्लंघन हुआ। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार का निषेध) विनियम, 2003 (संक्षेप में विनियम 2003) के प्रावधान। नतीजतन, अपीलकर्ता और अन्य निदेशकों को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया कि उन्होंने सेबी अधिनियम की

धारा 12 ए और विनियमन 3(बी), 3(सी), 3(डी), 4(1), 4(2) का उल्लंघन किया है। विनियम 2003 के (ए), 4(2)(ई), 4(2)(एफ), 4(2)(के), 4(2)(आर) और कारण बताने के लिए निर्देशित किया गया कि उचित समझे जाने वाले उचित निर्देश क्यों दिए जाएं और विनियम 2003 के विनियम 11 के साथ पठित सेबी अधिनियम की धारा 11, 11 बी और 11 (4) के तहत उचित उनके खिलाफ जारी नहीं किया जाएगा।

4. अपीलकर्ता ने 3 फरवरी, 2010 के पत्र के माध्यम से कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि कोई अनियमितता नहीं थी और कंपनी के प्रबंध निदेशक और प्रधान अधिकारी उस संबंध में एक विस्तृत जवाब भेजेंगे। बाद में, सेबी (न्याय निर्णय अधिकारी द्वारा जांच करने और जुर्माना लगाने की प्रक्रिया) नियम, 1995 के नियम 4(1) के तहत 8 अप्रैल, 2010 को एक नोटिस निदेशकों को यह बताने के लिए जारी किया गया था कि क्यों न धारा 15 के तहत जुर्माना लगाया जाए। अधिनियम के प्रावधान के कथित उल्लंघन के लिए सेबी अधिनियम।

5. अपीलकर्ता ने यह कहते हुए एक विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया कि यह कंपनी के प्रबंध निदेशक और प्रधान अधिकारी थे जो कंपनी के संचालन, वित्त और लेखा, सचिवीय और अनुपालन, कानूनी सेवाओं, तकनीकी सेवाएं सहित दिन-प्रतिदिन के मामलों के प्रभारी थे। अपीलकर्ता के अनुसार, यह कहा गया था, हालांकि कंपनी का पूर्णकालिक निदेशक केवल कंपनी के मानव संसाधन विभाग को संभाल रहा था और कर्मियों की

भर्ती, प्रशिक्षण और टीम निर्माण में पूरी तरह से तल्लीन था। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि उन्होंने वित्तीय मामलों में केवल ऑडिटर के बयानों पर भरोसा किया था और इसलिए सेबी अधिनियम और विनियम 2003 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं थे। अपीलकर्ता को 30.8.2010 को व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी गई थी। अपीलकर्ता द्वारा दायर लिखित निवेदन दिनांक 15.9.2010 पर भी सेबी द्वारा विचार किया गया। बोर्ड ने निम्नलिखित विशिष्ट उल्लंघन देखे

क) काल्पनिक प्रविष्टियों द्वारा हेरफेर किए गए खाते।

बी) स्टॉक एक्सचेंज को गलत खुलासे किए।

ग) जांच में सहयोग नहीं किया।

घ) कुछ खातों का रखरखाव नहीं किया।

6. तथ्यों पर अधिकारी ने पाया कि उपरोक्त सभी -उल्लेखित उल्लंघन स्थापित किए गए थे। नतीजतन, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य (डब्ल्यू.टी.एम) ने सेबी की धारा 19 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माना कि निदेशकों को सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 12 ए और विनियमन 3 (बी), 3 के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया था। (सी), 3(डी), 4(1), 4(2)(ए), 4(2)(ई), 4(2)(एफ), 4(2)(के), 4(2) (आर) विनियम 2003 के। तब सेबी के डब्ल्यू.टी.एम ने, सेबी अधिनियम की धारा 11, 11बी और 11(4) के साथ पठित धारा 19 और विनियम 2003 के

विनियम 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया। अपीलकर्ता और अन्य निदेशकों को किसी भी तरह से प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या व्यवहार करने या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने और किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक होने से क्रमशः दो साल और तीन साल की अवधि के लिए।

7. निर्णायक अधिकारी ने यह भी माना कि अपीलकर्ता और अन्य ने सेबी अधिनियम की धारा 12 ए और विनियमन 3(बी), 3(सी), 3(डी), 4(1), 4(2)(ए) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। विनियम 2003 के 4(2)(ई), 4(2)(एफ), 4(2)(के), 4(2)(आर) और यह विचार किया कि अपीलकर्ता और अन्य निदेशक मौद्रिक के लिए उत्तरदायी हैं सेबी अधिनियम की धारा 15 एच.ए. के तहत जुर्माना, जिसके तहत अपीलकर्ता पर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया था।

8. उपरोक्त आदेश, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, ट्रिब्यूनल द्वारा एक अपील में पुष्टि की गई थी, जिसकी वैधता इस अपील का विषय है।

9. हम इस अपील में विचार के लिए उठने वाले विभिन्न कानूनी मुद्दों की जांच करने से पहले यह संकेत देना चाहेंगे कि जांच से पता चला है कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर त्रैमासिक रिपोर्ट में शामिल वित्तीय परिणामों में कंपनी के राजस्व लाभ, सुरक्षा जमा और के बड़े हुए आंकड़े

शामिल थे। प्राप्य इसके अलावा, कंपनी के वित्तीय परिणामों में हेरफेर के परिणामस्वरूप कंपनी के शेयरों की कीमत में वृद्धि हुई और प्रमोटरों ने वित्तीय संस्थानों से पर्याप्त धन जुटाने के लिए अपने शेयरों को गिरवी रख दिया।

10. हम इस मामले के तथ्यों के साथ-साथ कानून को भी इस बिंदु पर प्रदर्शित करना चाहते हैं कि बाजार का दुरुपयोग अब भारत के सुरक्षा बाजार में एक आम बात बन गई है और यदि उचित तरीके से इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो इसके परिणामस्वरूप हार होगी। सेबी अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, पूंजी बाजार में हाल के दिनों में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से जनता की बढ़ती भागीदारी के कारण। निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करके पूंजी बाजार में निवेशकों का विश्वास काफी हद तक कायम रखा जा सकता है।

11. इस बिंदु पर कानून की जांच करने से पहले, हम यह प्रदर्शित करना चाहेंगे कि कंपनी और उसके निदेशकों ने कंपनी के राजस्व लाभ, सुरक्षा जमा और प्राप्य के आंकड़े कैसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए, जिन पर निवेशकों द्वारा निवेश निर्णय लेने के लिए भरोसा किया गया था। तथ्यों से यह भी पता चलता है कि निदेशकों ने अपने शेयर गिरवी रखे थे और बढ़े हुए वित्तीय परिणामों के आधार पर शेयरों की कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ा दी

थीं, जिससे उन्हें अधिक मात्रा में धन जुटाने में मदद मिली जो अन्यथा संभव नहीं होता।

12. 31 मार्च 2007 को समाप्त तिमाही से 31 मार्च 2009 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के तिमाही अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम निम्नलिखित विवरण दर्शाते हैं

particulars	For the quarter ended in (in Rs. Lakh)									
	Marc h 31, 2007	June 30, 2007	Sep 30, 2007	Dec31, 2007	Marc h 31, 2008	June 30, 2008	Sep 30, 2008	Dec31, 2008	Marc h 31, 2009	
net sales	675	1227	1441	23141.	2455	2501.	2522	13794.	806	
	6.89	1.43	8.79	87	6.12	87	5.72	81	9.04	
other income	23.2	13.6	231.7	152.90	144.0	12.94		2.08		
	4	8	5		5					

total	678	1228	1465	23294	2470	2502	2522	13796.	806
incom e	0.13	5.11	0.54	.77	0.17	7.81	5.72	89	9.04
total	6122	9936	1251	19718.	2236	2288	2347	12997.	6859
expen diture	.60	.44	3.42	54	6.93	6.72	8.48	58	.02
Net	583.	1600	1511.	2986.	-	1349.	870.	-	-
profit / loss	47	.77	31	50	311.2 2	72	42	7474. 35	8527 .25
Equity	282	2827	2827	2827.	2827	2827	2827	2827.	2827
	7.64	.65	.65	65	.65	.65	.65	65	.65
Face value of shares (in Rs.)	10	10	10	10	10	10	10	10	10

13. उपरोक्त तथ्य और आंकड़े दर्शाते हैं कि 30 जून 2007 को समाप्त तिमाही के लिए शुद्ध बिक्री पिछली तिमाही की तुलना में दोगुनी हो गई। बाद की तिमाहियों में, 30 सितंबर, 2008 को समाप्त तिमाही तक, ऊपर की ओर रुझान जारी रहा और 31 दिसंबर, 2008 को समाप्त तिमाही में, शुद्ध बिक्री के आंकड़ों में अचानक गिरावट आई (31 दिसंबर, 2008 को समाप्त तिमाही के लिए शुद्ध बिक्री के आंकड़े) 2008 में पिछली तिमाही की तुलना में लगभग 45 प्रतिशत की गिरावट आई थी)।

14. कंपनी ने उक्त तिमाही में 74.74 करोड़ रुपये का घाटा भी दिखाया. 31 मार्च 2009 को समाप्त तिमाही के लिए, कंपनी फिर से का घाटा दिखाया। 85.37 करोड़. 31 मार्च 2008 को समाप्त तिमाही को छोड़कर 30 जून 2008 को समाप्त तिमाही तक कुल आय के साथ शुद्ध लाभ के आंकड़ों में भी वृद्धि हुई।

15. यह बताया गया कि सेबी ने वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए कंपनी के खातों की पुस्तकों का सत्यापन किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि थिएटर आय, थिएटर प्राप्य और थिएटर के संबंध में कंपनी द्वारा उचित खातों और सहायक दस्तावेजों का रखरखाव किया गया था या नहीं। सुरक्षा जमा और क्या लिस्टिंग समझौते के अनुसार कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को किए गए वित्तीय खुलासे कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं।

16. सेबी की जांच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए कुल राजस्व रु. 749.30 करोड़ रुपये की आय शामिल है। सिनेमाघरों से 549.58 करोड़ जो इस प्रकार बताया गया है

Region	From PSTL Theatres	From non PSTL Theatre	Total Revenue from theatres
Tamilnadu	303.46	41.51	344.97
Andhra pradesh	74.66	62.04	136.70
karnataka	45.86	7.60	53.45
kerala	12.95		12.95
Others	0.28	1.23	1.52
Total	437.21	112.18	549.58

17. थिएटर की आय पर रु. तमिलनाडु क्षेत्र से 303.46 करोड़ रुपये में संबंधित समेकित डेबिट थिएटर कलेक्शन रिसीवेबल अकाउंट के साथ 244 करोड़ रुपये की समेकित क्रेडिट प्रविष्टियाँ शामिल थीं। खाते में अप्रैल 2008 के बाद से कोई आय नहीं दिखाई गई। उन प्रविष्टियों के संबंध में जर्नल वाउचर में दैनिक संग्रह रिपोर्ट संख्या, थिएटर का नाम आदि जैसी कोई भी जानकारी नहीं थी। प्राप्तियों को सामग्री की लागत के विरुद्ध

समायोजित किया गया था, अग्रिम/सुरक्षा जमा खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था या अप्राप्त रखा गया था। 31 मार्च 2008 को, तमिलनाडु क्षेत्र से कंपनी की कुल प्राप्य राशि रु. 38.58 करोड़. उसमें से 162 थिएटरों पर 2.19 करोड़ रुपये बकाया थे और बाकी 2.19 करोड़ रुपये थे। केवल एक खाते में 36.39 करोड़ रुपये बकाया हैं, जिसमें थिएटर के अनुसार विवरण शामिल नहीं है। इसके अलावा यह भी देखा गया कि आंध्र प्रदेश में अपने थिएटरों से प्राप्त 75 करोड़ रुपये की पूरी राशि का हिसाब-किताब एकल जर्नल वाउचर द्वारा किया गया था, जिसके पास उन समेकित प्रविष्टियों या जर्नल वाउचर के समर्थन में कोई अन्य सहायक दस्तावेज नहीं था, बावजूद इसके कि इसे प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था। ये तथ्य सेबी को इस निष्कर्ष पर ले गए कि उन राजस्वों ने 2007-08 की वार्षिक रिपोर्ट में बढ़े हुए आंकड़ों का खुलासा किया और इस तरह निवेशकों को गुमराह किया।

18. कंपनी ने 30 जनवरी, 2009 को स्टॉक एक्सचेंजों को यह नहीं बताया कि उसने 30 जून, 2008 तक 802 थिएटरों के साथ समझौता किया था। 802 समझौतों में से, कंपनी सेबी अधिकारियों को केवल 257 मूल समझौते दिखा सकी, जिससे सेबी को यह निष्कर्ष निकालना पड़ा। शेष 545 समझौते कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। फर्जी राजस्व को थिएटर संग्रह प्राप्य में बदल दिया गया था, जिसे बदले में सुरक्षा जमा में बदल दिया गया था। यह देखा गया कि सुरक्षा जमा वास्तविक नहीं थे, लेकिन

बैलेंस शीट में प्राप्ति को छिपाने के लिए बनाए गए थे क्योंकि छह महीने की अवधि के लिए बकाया प्राप्ति को अनिवार्य रूप से इसकी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट किया जाना था। इसलिए सेबी ने निष्कर्ष निकाला कि कंपनी ने इस आशय की झूठी कॉर्पोरेट घोषणा की थी कि उसने 802 थिएटरों के साथ समझौता किया था और निवेश करने वाली जनता को गुमराह किया था।

19. अपीलकर्ता का मुख्य बचाव यह था कि, हालांकि वह कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक और प्रमोटर थे, फिर भी कंपनी के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन में शामिल नहीं थे और वह मानव संसाधन विभाग की देखभाल कर रहे थे। कंपनी। इसके अलावा, यह भी कहा गया था कि वित्तीय विवरण, खाते आदि तैयार किए गए थे और वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत ऑडिट किए गए थे, ऑडिट समितियों द्वारा सत्यापित किए गए थे और प्रबंध निदेशक द्वारा समीक्षा की गई थी और कंपनी में, प्रत्येक निदेशक की भूमिका सीमित थी। उनके संचालन का क्षेत्र और कंपनी के मामलों के संपूर्ण प्रभार और नियंत्रण में एक निदेशक को रखने का कोई औचित्य नहीं था। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि लेखा परीक्षक खातों और वित्त में अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसलिए, जिन निदेशकों के पास खातों और वित्त की जटिलताओं की कोई विशेषज्ञता या ज्ञान नहीं है, उनके लिए उन पर संदेह करने या उनके बारे में निर्णय लेने का कोई कारण नहीं था। निर्णय ऐसी परिस्थितियों में, यह तर्क दिया गया था कि उन्हें प्रतिभूतियों

को खरीदने, बेचने या व्यवहार करने या प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने से रोकने या जुर्माना लगाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि जानबूझकर कोई असत्य बयान देने में अपीलकर्ता की ओर से कोई आपराधिक इरादा नहीं है। या झूठे रिकॉर्ड तैयार करना और कंपनी के खाते और वित्त तैयार करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है।

20. इस तरह के तथ्य और आंकड़े विवाद में नहीं हैं और बचाव पक्ष यह है कि बयानों का वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत ऑडिट किया गया था और परिणामस्वरूप, यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलकर्ता ने सेबी अधिनियम के प्रावधानों या विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। 2003.

21. आइए अब हम अपीलकर्ता द्वारा उल्लंघन किए गए विभिन्न प्रावधानों और उसके परिणामों के दायरे की जांच करें तों. धारा 12 ए सेबी अधिनियम के अध्याय वीए में आती है जो इस प्रकार है

“जोड़-तोड़ और भ्रामक उपकरणों का निषेध, अंदरूनी व्यापार और प्रतिभूतियों या नियंत्रण का पर्याप्त अधिग्रहण, जोड़-तोड़ और भ्रामक उपकरणों का निषेध, अंदरूनी व्यापार और प्रतिभूतियों या नियंत्रण का पर्याप्त अधिग्रहण।

12 ए. कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से -

(ए) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित किसी भी प्रतिभूतियों के मुद्दे, खरीद या बिक्री के संबंध में, इस अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी भी चालाकी या भ्रामक उपकरण या युक्ति का उपयोग या नियोजित करना। उसके तहत बनाए गए नियम।

(बी) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों के मुद्दे या लेनदेन के संबंध में धोखाधड़ी करने के लिए किसी भी उपकरण, योजना या चालाकी का इस्तेमाल नहीं करेगा।

(सी) किसी ऐसे कार्य, अभ्यास, व्यवसाय के पाठ्यक्रम में संलग्न होना जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों में लेनदेन के संबंध में किसी भी व्यक्ति पर धोखाधड़ी या धोखे के रूप में संचालित होता है या संचालित होगा। इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों का उल्लंघन।

(डी) अंदरूनी व्यापार में संलग्न।

(ई) सामग्री या गैर-सार्वजनिक जानकारी रखते हुए प्रतिभूतियों में सौदा करना या ऐसी सामग्री या गैर-सार्वजनिक जानकारी को किसी अन्य व्यक्ति को संप्रेषित करना, इस तरीके से जो इस

अधिनियम के प्रावधानों या बनाए गए नियमों या विनियमों का उल्लंघन है। उसके तहत।

(एफ) इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी के प्रतिशत से अधिक किसी भी कंपनी या प्रतिभूतियों का नियंत्रण प्राप्त करना, जिनकी प्रतिभूतियां किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने का प्रस्ताव है।

22. धारा 12ए को विनियम 2003 के विभिन्न प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। विनियम 2003 का अध्याय प्पू प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के निषेध से संबंधित है और अध्याय प्पू जांच से संबंधित है। सेबी ने 2003 विनियमों के विनियम 3 और 4 के उल्लंघन पर भी ध्यान दिया है, जो इस प्रकार हैं:

“सिक्योरिटीज़ बाज़ार से संबंधित धोखाधड़ीपूर्ण और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध

3. प्रतिभूतियों में कुछ लेन-देन पर कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध नहीं लगाएगा।

क) फर्जी तरीके से प्रतिभूतियों को खरीदना, बेचना या अन्यथा लेनदेन करना;

ख) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित किसी भी सुरक्षा के मुद्दे, खरीद या बिक्री के संबंध में, अधिनियम या नियमों या विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी भी हेरफेर या भ्रामक युक्ति या युक्ति का उपयोग या नियोजित करना वहाँ के अंतर्गत बनाया गया;

ग) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों के लेनदेन या जारी करने के संबंध में धोखाधड़ी करने के लिए किसी भी उपकरण, योजना या चालाकी का उपयोग करना;

घ) किसी ऐसे कार्य, अभ्यास, व्यवसाय के पाठ्यक्रम में संलग्न होना जो प्रतिभूतियों के किसी भी लेनदेन या जारी करने के संबंध में किसी भी व्यक्ति पर धोखाधड़ी या धोखे के रूप में संचालित होता है या संचालित होगा जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित है। अधिनियम के प्रावधान या इसके तहत बनाए गए नियम और विनियमरू

4. चालाकी, धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध

1) विनियम 3 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई भी व्यक्ति प्रतिभूतियों में धोखाधड़ी या अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल नहीं होगा।

2) प्रतिभूतियों में लेनदेन को धोखाधड़ी या अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाएगा यदि इसमें धोखाधड़ी शामिल है और इसमें निम्नलिखित में से सभी या कोई भी शामिल हो सकता है -

क) ऐसे कार्य में लिप्त होना जो प्रतिभूति बाजार में व्यापार का गलत या भ्रामक स्वरूप पैदा करता है;

बी) ३.. (डी)३.. ई) सुरक्षा की कीमत में हेरफेर करने वाला कोई भी कार्य या चूक;

च) प्रतिभूतियों में लेनदेन करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों में व्यापार करने से पहले या उसके दौरान कोई ऐसी जानकारी प्रकाशित करना या प्रकाशित करना या रिपोर्ट करना या रिपोर्ट करवाना जो सत्य नहीं है या जिसे वह सत्य नहीं मानता है। (जी) (ज) {{1} {1} (के) एक विज्ञापन जो भ्रामक है या जिसमें विकृत तरीके से जानकारी शामिल है और जो निवेशकों के निर्णय को प्रभावित कर सकता है।

(1)

(पी)

(क्यू).

झूठी या भ्रामक खबरें फैलाना जो प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद को प्रेरित कर सकती हैं।”

23. उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य और उद्देश्य बाज़ार में हेरफेर पर अंकुश लगाना है। पाल्मर्स कंपनी कानून, 25 वां संस्करण (2010), खंड 2, पृष्ठ 11097 पर कहा गया है ष्बाजार में हेरफेर को आम तौर पर आपूर्ति और मांग की सामान्य बाजार शक्तियों के संचालन में अनुचित हस्तक्षेप के रूप में माना जाता है और इस प्रकार अखंडता और दक्षता को कमजोर करता है। बाजार गॉवर एंड डेविस - आधुनिक कंपनी कानून के सिद्धांत, 9 वां संस्करण (2012) पृष्ठ 1160 पर भी देखें।

24. सेबी अधिनियम के अध्याय 4 ए में निहित दंड प्रावधानों का भी संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें हम मुख्य रूप से धारा 15 एचए से संबंधित हैं जो धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए दंड से संबंधित है और धारा 15 जे जो डी दंड की मात्रा का निर्णय करते समय निर्णायक अधिकारी द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले कारकों के साथ भी। वे प्रावधान आसान संदर्भ के लिए नीचे दिए गए हैं

“15 एचए. कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए जुर्माना.- यदि कोई व्यक्ति प्रतिभूतियों से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त होता है, तो वह पच्चीस करोड़ रुपये या ऐसी प्रथाओं से प्राप्त लाभ की राशि का तीन गुना, जो भी हो, के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा। से ज़्यादा ऊँचा।

“15 जे. न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले कारक- धारा 15 के तहत जुर्माने की मात्रा का निर्णय करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी को निम्नलिखित कारकों पर उचित ध्यान देना होगा, अर्थात् (ए) डिफॉल्ट के परिणामस्वरूप किए गए अनुपातहीन लाभ या अनुचित लाभ की राशि, जहां भी मात्रा निर्धारित की जा सकती है।

(बी) डिफॉल्ट के परिणामस्वरूप किसी निवेशक या निवेशकों के समूह को हुई हानि की राशि।

(सी) डिफॉल्ट की दोहरावदार प्रकृति।”

25. सहारा इंडिया रियल एस्टेट कारपोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड और अन्य (2013) 1 एससीसी 1 में, इस न्यायालय ने देखा है कि यद्यपि भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 अंग्रेजी कंपनी अधिनियम, 1948 पर आधारित था, नहीं हमारे कंपनी

कानून में सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों और अवधारणाओं को शामिल करने के प्रयास किए गए हैं। हालाँकि, हाल ही में, अंग्रेजी कंपनी अधिनियम और संबंधित विधानों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956, साथ ही सेबी अधिनियम, 1992 और उसमें बनाए गए नियमों और विनियमों में कुछ संशोधन करके कुछ प्रयास किए गए हैं। जब हम सेबी अधिनियम के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी से संबंधित विनियमों की व्याख्या करते हैं, तो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना होगा। उदाहरण के लिए, सेबी अधिनियम में, किसी पंजीकृत कंपनी द्वारा खातों की उचित किताबें रखने का कोई प्रावधान नहीं है।

26. कंपनी अधिनियम की धारा 209 कहती है कि प्रत्येक कंपनी को पंजीकृत कार्यालय में खातों की उचित किताबें रखनी होंगी। खातों की किताबें इस प्रकार रखी जानी चाहिए कि कंपनी के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके और लेनदेन की व्याख्या की जा सके। बेशक, कंपनी के लेखा परीक्षकों को यह जांचना चाहिए कि क्या कंपनी ने नियमों के अनुसार उचित लागत लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखा है। जिन कंपनियों की प्रतिभूतियों का सार्वजनिक बाजार में कारोबार होता है, उनके लिए यह सामान्य कानून है कि कंपनी की प्रतिभूतियों के सही और सटीक मूल्य निर्धारण और बाजार के आधिकारिक संचालन के लिए कंपनी के बारे में जानकारी का खुलासा महत्वपूर्ण है। कंपनी अधिनियम की धारा

210 में कहा गया है कि कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में, निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष के अंत में एक बैलेंस-शीट और लाभ और हानि खाता रखना आवश्यक होता है।

27. सेबी और संबंधित कंपनियों के बीच लिस्टिंग समझौते के खंड 41 में कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत करने और निर्धारित प्रारूप में तिमाही आधार पर अनऑडिटेड वित्तीय परिणाम प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। कंपनी अधिनियम की धारा 55 ए सेबी की शक्तियों से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि इसमें उल्लिखित कुछ प्रावधान, जहां तक वे प्रतिभूतियों के जारी करने और हस्तांतरण और सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में लाभांश का भुगतान न करने से संबंधित हैं, सेबी द्वारा प्रशासित होंगे। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि कंपनी को खातों की किताबें कैसे रखनी हैं, खाते की लेखापरीक्षा आदि के संबंध में भी कंपनी अधिनियम में जगह मिलती है, इसलिए प्रबंध निदेशकों की योग्यता और अयोग्यता भी होती है।

28. हमने इस मामले में देखा कि कंपनी के निदेशकों ने 2003 विनियमों के विनियम 3 और 4 के साथ पढ़े जाने वाले सेबी अधिनियम की धारा 12 ए के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया था। जिन कंपनियों की प्रतिभूतियों का सार्वजनिक बाजार में कारोबार होता है, कंपनी की प्रतिभूतियों के सटीक मूल्य निर्धारण और बाजार के कुशल संचालन के लिए कंपनी के बारे में जानकारी का खुलासा महत्वपूर्ण है।

कॉर्पोरेट प्रशासन और निदेशक

29. कंपनी अधिनियम के विनियमों के साथ पढ़ा जाने वाला सेबी अधिनियम यह संकेत देगा कि सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशकों के दायित्व विशेष रूप से कठिन हैं, खासकर जब निदेशक मंडल कंपनी के प्रदर्शन के लिए शेयरधारकों के लिए और इसके उत्पादन के लिए भी खुद को जवाबदेह बनाता है। खाते और वित्तीय विवरण, खासकर जब कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी हो।

30. कंपनी के निदेशक या प्रभारी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी भी प्रतिभूतियों के मुद्दे, खरीद या बिक्री के संबंध में सेबी अधिनियम या के उल्लंघन में किसी हेरफेर या भ्रामक उपकरण या युक्ति का उपयोग या नियोजित करते हैं। इसके तहत बनाए गए विनियमों को आवश्यक रूप से अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाना चाहिए जो निवेशक की सुरक्षा और बाजार के दुरुपयोग से बचने के लिए बिल्कुल आवश्यक है।

31. तथ्यों ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि कंपनी ने झूठी कॉर्पोरेट घोषणा की थी जिसमें कहा गया था कि उसने 802 थिएटरों के साथ समझौता किया था और झूठी कॉर्पोरेट घोषणा ने अग्रिम, सुरक्षा जमा और आय से संबंधित गलत आंकड़े दिए थे। उन थिएटरों से संबंधित जो

अस्तित्वहीन नहीं थे। दिखाई गई जमाएँ वास्तविक नहीं थीं, बल्कि बैलेंस शीट में प्राप्ति को छिपाने के लिए केवल बही प्रविष्टियाँ थीं।

32. वार्षिक रिकॉर्ड और रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी निदेशकों पर डाली जाती है और उन खातों में शसच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रतिबिंबित होना चाहिए। निदेशकों का प्रमुख दायित्व यह है कि वे खातों को तभी मंजूरी दें जब वे संतुष्ट हों कि वे प्रासंगिक अवधि के लिए लाभ या हानि और कंपनी की सही वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष विवरण देते हैं।

33. हालांकि कंपनी एक कानूनी इकाई है, वह स्वयं कार्य नहीं कर सकती, वह केवल अपने निदेशकों के माध्यम से ही कार्य कर सकती है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे कंपनी की ओर से अपनी शक्ति का प्रयोग अत्यंत सावधानी, कौशल और परिश्रम से करें। यह न्यायालय यह बताते हुए कि किसी कंपनी के निदेशक का कर्तव्य क्या है, आधिकारिक परिसमापक बनाम पी.ए. तेंडोलकर (1973) 1 एससीसी 602 में कहा गया है कि एक निदेशक को कंपनी के प्रबंधन के साथ इतने करीब से और इतने लंबे समय तक व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहने के लिए दिखाया जा सकता है कि उसे न केवल संज्ञान में लिया जाएगा, बल्कि धोखाधड़ी के लिए उत्तरदायी भी माना जाएगा। कंपनी के व्यवसाय का संचालन भले ही उसके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से बेईमानी का कोई विशेष कार्य न किया गया हो। वह उस पर अपनी आँखें बंद नहीं कर सकता जो कंपनी के

मामलों की सतही तौर पर जाँच करने वाले हर किसी के लिए स्पष्ट होनी चाहिए।

34. इस मामले में तथ्यों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संबंधित कंपनी के निदेशक उचित देखभाल और परिश्रम करने के अपने कर्तव्य में विफल रहे और कंपनी को आंकड़े गढ़ने और झूठे खुलासे करने की अनुमति दी। तथ्यों से संकेत मिलता है कि उन्होंने राजस्व, लाभ, प्राप्य, जमा आदि में कई लाल झंडों को नजरअंदाज कर दिया है, जो एक विवेकशील व्यक्ति के ध्यान से बच नहीं जाना चाहिए था। उदाहरण के लिए, जून 2007 को समाप्त तिमाही में लाभ पिछली तिमाही की तुलना में तीन गुना अधिक था, दिसंबर 2007 को समाप्त तिमाही में यह पिछली तिमाही की तुलना में दोगुना हो गया। इसके अलावा, सुरक्षा जमा यानी रु. में अनुपातहीन वृद्धि हुई। सितंबर 2007 में 36.05 करोड़ रु. इसी अवधि के दौरान सिनेमाघरों की संख्या में वृद्धि की तुलना में दिसंबर 2007 में 270.38 करोड़ रु. उन्होंने बोर्ड की बैठकों में भाग लिया है और उन आयोगों और चूकों के बारे में जानकारी रखते हैं।

प्रतिभूति बाज़ार - बाज़ार का दुरुपयोग

35. बाजार के दुरुपयोग की रोकथाम और बाजार की अखंडता का संरक्षण प्रतिभूति कानून की पहचान है। विनियम 2003 के विनियम 3 और 4 के साथ पठित धारा 12 ए का उद्देश्य अनिवार्य रूप से बाजार की

अखंडता को बनाए रखना और बाजार के दुरुपयोग को रोकना है। सेबी अधिनियम का उद्देश्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और विकास को बढ़ावा देना और प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना है, ताकि प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित, स्वस्थ विकास को बढ़ावा दिया जा सके और निवेशकों की सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। प्रतिभूति बाजार सूचना तक निःशुल्क और खुली पहुंच पर आधारित है, बाजार की अखंडता उस गुणवत्ता और तरीके पर आधारित है जिस पर इसे बाजार में उपलब्ध कराया जाता है। शबाजार का दुरुपयोग आर्थिक विकास को खराब करता है और निवेशकों का विश्वास खत्म करता है। बाजार के दुरुपयोग का अर्थ चालाकीपूर्ण और भ्रामक उपकरणों के उपयोग से है, जो गलत या भ्रामक जानकारी देता है, ताकि निवेशकों को गलत आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जो कि दुरुपयोग करने वालों के लिए गलत माना जाता है। पहले उल्लिखित वैधानिक प्रावधान उन स्थितियों से निपटते हैं जहां एक व्यक्ति, जो प्रतिभूतियों में व्यापार करता है, किसी कार्रवाई के प्रभाव का लाभ उठाता है, बाजार पर प्रत्याशित प्रभाव पर हेरफेर कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप कृत्रिमता का निर्माण होता है। इसे कंपनी के राजस्व, मुनाफे, सुरक्षा जमा और प्राप्य को बढ़ाकर हासिल किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के शेयरों की कीमत बढ़ जाती है। फिर निवेशकों को उपरोक्त उपकरणों का उपयोग करके उन हेरफेर

किए गए बढ़ाए गए परिणामों पर अपने निवेश निर्णय लेने का लालच दिया जाता है, जो बाजार का दुरुपयोग होगा।

36. हमने तथ्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से पाया है कि कंपनी के निदेशकों ने कंपनी के राजस्व, लाभ, सुरक्षा जमा और प्राप्त के बढ़े हुए आंकड़े पेश करके कृत्रिमता पैदा की है और कंपनी के वित्तीय परिणामों में हेरफेर के परिणामस्वरूप कीमत में वृद्धि हुई है। कंपनी के शेयर में वृद्धि हुई और कंपनी के प्रमोटरों ने वित्तीय संस्थानों से पर्याप्त धन जुटाने के लिए अपने शेयर गिरवी रख दिए। इसलिए, अपीलकर्ता और अन्य का आचरण कपटपूर्ण था और प्रतिभूतियों से संबंधित उन्होंने जो प्रथाएं अपनाई थीं, वे अनुचित थीं, जिसके कारण सेबी अधिनियम की 15 जे के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 15 एचए में निहित दंड प्रावधान लागू हुए।

प्रकटीकरण और पारदर्शिता

37. आधुनिक कंपनी कानून के सिद्धांतों पर गॉवर और डेविस, 9 वें संस्करण (2012), पृष्ठ 751 पर, कंपनी अधिनियमों के तहत आवश्यक वार्षिक रिपोर्टिंग के दायरे और औचित्य पर अपने विचार इस प्रकार दोहराए गए हैं इस आधार पर कि पूर्व चेतावनी दी गई है कि कंपनी अधिनियम का अंतर्निहित मूल सिद्धांत प्रकटीकरण का है। यदि जनता और सदस्यों को कंपनी के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया, तो संस्थापक ने सोचा हमारे कंपनी कानून के जनक, एक

निश्चित ढाल होंगे। ढाल शायद उतनी मजबूत साबित नहीं हुई जितनी उन्होंने उम्मीद की थी और हाल के दिनों में, इसे आक्रामक हथियारों द्वारा समर्थित किया गया है।

38. कंपनी अधिनियम पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी पर खातों की किताबें रखने का दायित्व डालता है। पहले, यह सोचा गया था कि वार्षिक खातों का उत्पादन और इसकी तैयारी कंपनी द्वारा नियुक्त लेखा पेशेवर की होती है, जहां दो समूह जो बेहद रुचि रखते थे वे शेयरधारक और लेनदार थे। लेकिन परिदृश्य काफी हद तक बदल गया है, खासकर उस कंपनी के संबंध में जिसकी प्रतिभूतियों का सार्वजनिक बाजार में कारोबार होता है। इसलिए, कंपनी की प्रतिभूतियों के सटीक मूल्य निर्धारण और बाजार की अखंडता के लिए कंपनी के बारे में जानकारी का खुलासा महत्वपूर्ण है। कंपनी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को कंपनी के लेनदेन को दिखाना और समझाना चाहिए, इसे किसी भी समय उचित सटीकता के साथ वित्तीय स्थिति का खुलासा करना चाहिए, और निदेशकों को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना चाहिए कि बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते वैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे। वे वृत्तांत सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 में खंड (ए)(प्प) जोड़ा गया है जिसके तहत सेबी को सूचीबद्ध कंपनियों या ऐसे अधिकारियों के माध्यम से सूचीबद्ध होने

की इच्छुक कंपनियों के निरीक्षण की शक्ति भी दी गई है, जिन्हें इसके द्वारा अधिकृत किया जा सकता है।

39. जहां तक संबंधित कंपनी का सवाल है, खातों की किताबें टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रखी गई थीं और वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए प्रत्येक क्षेत्र/इकाई के लिए अलग-अलग खातों की किताबें रखी गई थीं। कथित तौर पर क्षेत्रों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में खातों की पुस्तकों का रखरखाव किया जाता था और वर्ष के अंत में वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने और ऑडिटिंग उद्देश्य के लिए, उन खातों की पुस्तकों को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में लाया जाता था। ऑडिटर्स ने बताया था कि उन किताबों का ऑडिट कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किया गया था। जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, 31 जनवरी 2008 को वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद, जिसमें 31.12.2007 को समाप्त तिमाही के लिए बढ़ा हुआ मुनाफा, राजस्व शामिल था, कंपनी के प्रबंध निदेशक, उनकी पत्नी और अपीलकर्ता ने मिलकर 72,75,455 शेयर गिरवी रखे थे। कंपनी ने विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ ऋण के रूप में 97.30 करोड़ रुपये जुटाए। हमने देखा है कि कंपनी के निदेशकों और मुख्य वित्तीय अधिकारियों ने कंपनी के जाली और भ्रामक परिणाम प्रकाशित किए थे, विभिन्न तिमाही वित्तीय परिणाम और वर्ष 2007-08 के वार्षिक परिणाम, स्टॉक-एक्सचेंजों को बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए थे। कंपनी के राजस्व, लाभ, सुरक्षा जमा और प्राप्य के आंकड़े और वे वित्तीय विवरण

जिन पर निवेशकों द्वारा निवेश निर्णय लेने में भरोसा किया गया था, जो कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं दर्शाते थे।

40. अपीलकर्ता ने यह रुख अपनाया है, कि भले ही वह पूर्णकालिक निदेशक था, फिर भी वह खातों और वित्त से परिचित नहीं था और केवल कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधन से निपट रहा था, इसलिए, उसने कोई धोखाधड़ी नहीं की थी निवेशकों को धोखा देने का इरादा. हमें इस विवाद को स्वीकार करना कठिन लगता है। अपीलकर्ता, माना जाता है कि, कंपनी का पूर्णकालिक निदेशक था, जहां तक वार्षिक खातों, बैलेंस-शीट और वित्तीय विवरण तैयार करने और वार्षिक आम बैठक में कंपनी के समक्ष रखने और रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल करने का संबंध था। कंपनियों के साथ-साथ सेबी के समक्ष, कंपनी के निदेशकों की अधिक जिम्मेदारी होती है, खासकर जब कंपनी एक पंजीकृत कंपनी हो। कंपनियों के निदेशकों, विशेष रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों के पास आंतरिक ज्ञान तक पहुंच होती है, जैसे कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभांश दरें, वार्षिक खाते आदि। निदेशकों से अपेक्षा की जाती है कि वे उन उद्देश्यों के लिए शक्तियों का उपयोग करें जिनके लिए उन्हें प्रदान किया गया है। कभी-कभी वे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं और गैरकानूनी लाभ के लिए जनता के सामने गलत प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

41. हमने संकेत दिया है, जहां तक इस मामले का संबंध है, बड़े हुए वित्तीय परिणामों के आधार पर कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई कीमतों पर उनके शेयरों को गिरवी रखने और उन पर ऋण जुटाने का आचरण यह संकेत देगा कि उन्होंने जानबूझकर और पूरी जानकारी के साथ अवैधता की थी और इसलिए एकटा एक्सटीरिया इंडिकेंट इंटिरियरा सीक्रेटा (जिसका अर्थ है बाहरी क्रियाएं आंतरिक रहस्यों को प्रकट करती हैं) का सिद्धांत पूरी ताकत से लागू होता है, एक सिद्धांत जिसे इस न्यायालय ने सहारा के मामले में लागू किया था।

42. तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति से ऊपर, हमारा विचार है कि सेबी ने अपीलकर्ता को उस आदेश की तारीख से दो साल की अवधि के लिए किसी भी तरह से किसी भी प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या व्यवहार करने से रोक दिया है, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार तक पहुंच और किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक होने से और न्यायनिर्णयन अधिकारी ने इसके तहत 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी अधिनियम की धारा 15 एच ए। अतः अपीलें खारिज की जाती हैं। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

चेतावनी

43. बाजार नियामक सेबी को चालाकीपूर्ण और भ्रामक उपकरणों, अंदरूनी व्यापार आदि में लिप्त कंपनियों और उनके निदेशकों से सख्ती से

निपटना होगा अन्यथा वे प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के अपने कर्तव्य में विफल हो जाएंगे। इस देश के लोगों को पता होना चाहिए कि आर्थिक अपराध एक गंभीर अपराध है, जिसे अगर उचित तरीके से नहीं निपटाया गया, जैसा कि होना चाहिए, तो न केवल देश की आर्थिक वृद्धि प्रभावित होगी, बल्कि वास्तविक निवेशकों द्वारा विदेशी निवेश का प्रवाह भी धीमा हो जाएगा और नुकसान भी होगा। भारत के प्रतिभूति बाजार पर कलंक। संदेश जाना चाहिए कि हमारा देश बाजार का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं करेगा और हम कानून के शासन द्वारा शासित हैं। सेबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धोखाधड़ी, छल, कृत्रिमता का इस देश के प्रतिभूति बाजार में कोई स्थान नहीं है और बाजार सुरक्षा हमारा आदर्श वाक्य है। सत्ता, पैसा और कंपनियों के प्रबंधन वाले लोग दुर्भाग्य से अक्सर हमारे समाज में अपनी कंपनियों के ग्राहकों और निवेशकों की तुलना में अधिक सम्मान पाते हैं। कंपनियां निवेशकों के योगदान से फल-फूल रही हैं लेकिन वे विभाजित हैं। इसलिए, सेबी का कर्तव्य है कि वह सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों और अंदरूनी सूत्रों के अवसरवादी व्यवहार के खिलाफ व्यक्तिगत और सामूहिक निवेशकों की रक्षा करे ताकि बाजार की अखंडता की रक्षा की जा सके।

44. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी यह गंभीर कर्तव्य है कि वे प्रतिभूति बाजार पर अपने पूर्वानुमानों में जनता, जो वर्तमान और संभावित निवेशक हैं, को गुमराह न करें। बेशक, किसी कंपनी की बाजार

स्थिति पर वास्तविक और ईमानदार राय का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन प्रतिभूतियों में स्थिति से लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से सुरक्षा बाजार में कंपनी की स्थिति पर मीडिया प्रक्षेपण कृत्रिमता पैदा करते हुए बाजार का दुरुपयोग होगा। सामान्य वास्तविक निवेशकों की सुरक्षा करना सेबी का कर्तव्य और दायित्व है और सेबी को सेबी अधिनियम के तहत ऐसा करने का अधिकार है ताकि सुरक्षा बाजार को प्रतिभूतियों में व्यापार करने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया जा सके।

बी.बी.

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से न्यायिक अधिकारी वृष्टि विज (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।
